भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3250

जिसका उत्तर 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

07 चैत्र, 1947 (शक)

डेटा केंद्रों में निवेश को बढ़ावा देना

3250. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के लिए डेटा सेंटरों में निवेश को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा टियर-।। और टियर-।।। शहरों में डेटा सेंटरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खनिजों, भूमि और जल के लिए बोली-युद्ध को रोकने और डेटा सेंटरों का सतत विस्तार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार डेटा सेंटरों को उनके संचालन के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) देश में डाटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डाटा सेंटर उद्योग और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है।

डेटा सेंटर के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत, डेटा सेंटर सहित विभिन्न अवसंरचना विकास गतिविधियों को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म पर मैप किया जा रहा है। यह भूमि, बिजली/हरित ऊर्जा आदि जैसी बुनियादी संरचना की उपलब्धता के आधार पर संभावित डेटा सेंटर स्थानों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

डेटा सेंटर उद्योग की सुविधा के लिए, सरकार ने अवसंरचना की हार्मोनाइज्ड लिस्ट के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) लोड के न्यूनतम 5 मेगावाट (एमडब्लू) क्षमता वाले डेटा सेंटर को शामिल करने के लिए दिनांक 11.10.2022 को राजपत्र अधिसूचना जारी की।

किसी विशेष स्थान पर डाटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय संबंधित डाटा सेंटर डेवलपर्स द्वारा उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है। डेटा सेंटर के संदर्भ में, खनिजों, भूमि और पानी के लिए बोली -युद्ध की कोई घटना सामने नहीं आई है। इसके अलावा, सरकार डेटा सेंटर उद्योग को उनके संचालन के लिए हरित ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रही है ।

****